each of the blocks over a period of three years.

(c) and (d) In Maharashtra State a total of 9 blocks have been selected under this programme. This district-wise names of the block are given below:—

District	Block
1. Solapur	Mangalwedha
2. Beed	Kej
3. Nasik	Malegaon
4. Pune	Junnar
5. Bhandra	Salekasa
6. Nagpur	Ramtek
7 Yavatmal	Kalamb
8. Amravathi	Chikhaldhara
9. Wardha	Seloo

Though 4 institutions have been approved for implementation of this Programme in Ramtek Block of Nagpur District, only one institution, i.e. Dhanalakshmi Khadi Gramodyog Sanstha, Wardha has availed of financial assistance during the year 1995-96. This Institution is only implementing a scheme on cotton Khadi.

(e) and (f) Under this programme, KVIC has fixed a target of employment generation for 1000 persons in each block by the end of the 8th Five Year Plan.

मध्य प्रदेश के लिए मिट्टी के तेल का कोटा

787. श्री राघवजी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश हेतु मिट्टी के तेल का कितना मासिक कोटा स्वीकृत है और केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1996 के दौरान माहवार कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने हेतु कहा है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को 1996 के दौरान मिट्टी के तेल की माहवार आवंटित मात्रा और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मी० टन में)

माह	आवंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा
जनवरी	39935	41832
फरवरी	39935	41081
मार्च	42270	46501
अप्रैल	47047	43962
मई	42378	उपलब्ध नहीं
जून	42378	उपलब्ध नहीं
जुलाई	42378	उपलब्ध नहीं
अगस्त	42378	उपलब्ध नहीं

(ख) जी, नहीं। पिछले दो माह के दौरान ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 1995-96 के दौरान आवंटित मिट्टी के तेल की तुलना में 1996-97 के दौरान 6.1% की वृद्धि की अनुमति दी

है। 1996-97 के लिए राज्य को वार्षिक आवंटन की मात्रा 588539 मी० टन है।

Poor Conditions of Children in Remand and Juvenile Home

788. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report in the National Mail (Bhopal) dated May 28, 1996, attributable to National Human Rights Commission sources that children in 600 and odd remand and juvenile homes in the country are languishing in conditions that deprive them of basic rights; and

(b) if so, what steps have been and are being taken by Government to improve the living conditions in juvenile and remand homes and to ensure that the children's stay in such homes is curtailed to the minimum?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA) (a) Yes, Sir. However, the conditions of inmates is reasonably good. There is a set norm for providing clothing an bedding to the inmates once he is committed apart from the dietary intake fixed on the basis of caloric requirement. There is a team of Welfare Officers in each home to ensure fair distribution of above said articles.

(b) The implementation, of J.J. Act, 1996 which provides for the care, protection, treatment development and rehabilitation of neglected or delinquent juveniles and for the adjudication of certain matters relatiang to and disposition of, delinquent juveniles, rests with the State Governments/UT Administrations. Under this Act, Probation Officers are appointed by the State Government as per their requirement and Juvenile Welfare Boards & Courts are set up to expedite restoration of neglected juveniles to their parents/guardians.

As a follow up measure of the J J Act, 1986, Government of India is implementing a Scheme of Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustment to assist the State Government/UT Administration, for creating and strengthening of infrastructure. Under this Scheme, grant-in-aid is provided to State Government/UT Administration for construction of homes, upgradation of existing homes and maintenance of inmates on 50:50 basis.

In addition to above, the Central Government has been pursuing the State Government/UT Administrations to ensure successful implementation of the provisions of the J.J. Act and the Scheme of Prevention & Control of Juvenile Social Maladjustment from time to time.

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति

789. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में कोई वृद्धि हुई

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या रेलवे द्वारा उक्त कोयले को ढोने के लिए पर्याप्त वैगन उपलब्ध कराए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती वी सिंह) (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1994-95 1995-96 के दौरान विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति कोयले वास्तविक मात्रा (जिसमें मिडलिंग्स शामिल हैं), क्र 169.74 मिलियन टन और 187.27 मिलियन टन जोकि कोयले की मात्रा में 10.33% की वृद्धि को दर्श है।

(ग) और (घ) विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रेल द्वारा प्रेषण किए जाने वाले कोयले के संचलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि कुछ कोयला क्षेत्रों में वैगनों को उपलब्ध कराने में कठिनाइयां हुई है। किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1995-96 में रेलवे